

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता का नाम
1.	2525/2015	तेजा सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु।	श्री धीरज गुप्ता
2.	2526/2015	धन सिंह	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु।	श्री धीरज गुप्ता

आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा एवं श्री हेमन्त धारीवाल,
राजकीय अभिभाषकगण

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

- उपरोक्त दोनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से न्यायहित में अपील संख्या 2525/2015 तेजा सिंह बनाम राजस्थान राज्य की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, दोनों अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।
- अपील संख्या 2525/2015 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड-III के पद पर आदेश दिनांक 02.12.1985 से हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 03.12.1985 को कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी की सेवाएं नियुक्ति तिथि से नियमित की गई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर दिनांक 03.12.2012 से दिया जाना था, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नहीं करते हुए स्क्रीनिंग के पश्चात नियमितिकरण की दिनांक से की जा रही है, जो उचित नहीं है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:-

" It is therefore most humbly prayed this appeal may kindly be allowed for the record and after that and call examining the same the impugned action by which withholding the benefit of 27 years of the appellant may kindly be quashed and set aside and respondents be directed to grant the benefit of third selection Grade to the appellant by counting his services from the date of initial appointment i.e. 03.12.1985. In consequence arrears also be granted

with interest of 9% per annum. Heavy Cost of the appeal may kindly be awarded in favour of the appellant.

Any other order, which this Hon'ble Court deem just and proper may kindly be passed in favour of the appellant. "

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.12.1985 को अस्थायी तौर पर चयनित आशार्थी उपलब्ध होने या कार्यग्रहण करने की तिथी से 6 माह के लिए अथवा सत्रांत तक जो भी पहिले हो की शर्त के साथ अध्यापक के पद पर की गई। तदनुसार प्रार्थी ने दिनांक 03.12.1985 को पदभार ग्रहण किया तथा जिला स्थापना समिति जिला, परिषद चुरु द्वारा स्क्रीनिंग आदेश जारी किये जाने की तिथी से विधि अनुसार प्रार्थी की सेवाएं नियमित माने जाने के अनुसार और माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम् जगदीश नारायण चतुर्वेदी मे पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपीलार्थी बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लम्बे बिलम्ब बाद बिना और बिलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यो के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। जिला परिषद चुरु के स्क्रीनिंग और नियमितकरण आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Rajasthan Vs. Jagdish Narain Chaturvedi : (2009) 12 SCC 49 पारित विनिश्चय की पालना मे अपीलार्थी नियमित नियुक्ति संबधित जारी आदेश की दिनांक से ही विधि अनुसार लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है। उक्तानुसार अपील मय कोस्ट काबिल निरस्त योग्य है। पंचायत समितियों द्वारा शिक्षा विभाग मे स्थानान्तरित होकर आये कर्मचारियों की सेवाओ का नियमितकरण पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियमो मे आवश्यक संशोधन संबधित अधिसूचना कमांक 4 (11) पीएण्डजे/आरडी/पी/87/192 दिनांक 17.03.2009 अनुसार स्क्रीनिंग के बाद आदेश जारी होने की तिथि से ही अपीलार्थी लाभ प्राप्ति का अधिकारी है।
4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई रूप से हुई थी। नियुक्ति आदेश से स्पष्ट है कि नियुक्ति 6 माह के लिए या चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अथवा सत्रांत तक जो भी पहले हो,

तक की अवधि के लिए की गई थी। बाद में अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित की गई है।

5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of

seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह माना गया है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारिख नहीं हो सकती। अपीलार्थी की जो सेवाएं वर्ष 1990 से स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित की गई है, उसके पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी ने तदर्थ (ad-hoc) आधार पर दी थी, जो सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।
7. उपरोक्त दोनों अपीलों में हम अपीलार्थीगण के इन तर्कों से सहमत नहीं है कि अपीलार्थीगण की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाकर उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ दिलाया जाए। परिणामस्वरूप दोनों अपीलों में कोई बल नहीं होने अपीलें खारिज की जाती है।
8. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2525/2015 में एवं आदेश की प्रतिलिपि अन्य अपील संख्या 2526/2015 में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)